मुख्य शिफारिशें	की गई कार्यवाही
1. नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए इलाहाबाद एक्सचेंज का विस्तार	1. 1000 लाइनों का विस्तार कार्य मार्च, 1986 में पूरा किया गया।
2. सेवा में सुधार	2. आवश्यक कार्यवाई की गई है।
3. प्रत्येक ट्रंक-बोर्ड पोजीशन पर टेप-रिकार्डरों की फिटिंग करना	3. यह काम व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है।
4. इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज का आबंटन	4. वर्ष 1988–89 के लिए 5000 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आबंटित किया गया।
5. 13 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की सिफारिश	5. मार्च, 1986 में किये गये 1000 लाइनों के विस्तार के साथ प्रदान कर दिये गये है।
6. विद्युत गार्डिंग की व्यवस्था	6. यह व्यवस्था की जा चुकी है।
7. टेलीफोन डायरेक्टरी की बिक्री	7. बिक्री काउण्टर पर इसकी व्यवस्था की गई है।
8. 5000 लाइनों के अलावा इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का आगे आबंटन करना	8. वर्ष 1991, 1992 और 1993 के लिए (प्रत्येक वर्ष के लिए 1000 लाइनें) 3000 लाइनों का आबंटन किया गया है।
9. फाफामऊ और इलाहाबाद के बीच जंक्शन लाइनों में वृद्धि करना	9. इसका औचित्य नहीं पाया गया है।
10. कासबार एक्सचेंज को हटाना	10. कार्यकाल की समाप्ति से पहले इसको हटाना संभव नहीं है।
11. सलाहकार समिति का कामकाज हिंदी में करना	11. शुरू कर दिया गया है।
12. एक्सचेंज का विस्तार करके प्रतीक्षा सूची का निपटान करना	12. उपस्कर के आबंटन के अनुसार यह कार्य किया जा रहा है।

Import of banned/restricted insecticides by HIL

3356. DR. BAPU KALDATE:
SHRI ASHOK NATH VERMA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the management of Hindustan Insecticides Limited (A Government of India Enterprise) have taken policy decision not to import banned/restricted insecticides, fungicides, etc. for other private companies as being a canalised agency under import policy for 1988-1991 except for captive consumption, as other companies sell such products at exhorbitant prices with profit margin of 200 per cent;

(b) whether the Hindustan Insecticides Limited have received indents from private parties during the last nine months for import of banned/restricted items; if so, what are the details thereof;

(c) whether HIL has imported so far banned| restricted items for other companies in violation of Government directives; if so, what are the details thereof; and

(d) what is Government's reaction in the matter?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) No such decision has been taken by HIL management. Import is arranged by HIL on specific recommendation of Ministry of Agriculture in accordance with existing import export policy. Only those items can be imported which are registered for use in India.

(b) and (c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Increase in prices of medicines containing controlled bulk drugs as ingredients

3357. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of a number of medicines containing controlled bulk drugs as minor ingredients have been increased;

(b) if so, the names of those medicines along with the earlier and present price of each;

(c) whether these companies have taken the price approval;

(d) if so, the names of the companies and medicines;

(e) whether it is also a fact that a number of small scale units have increased the prices of their medicines based on controlled drugs falling under Category II;

(f) if so, the names of such medicines and their manufacturers as also the earlier and present price along with percentage change;

(g) what is the provision of DPCO under which all these prices have been increased; and

(h) the names of finished medicines where prices have gone up during the last three months along with the earlier and present price of each?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (d) and (h) The required details are quite voluminous and are not readily available. The time and efforts required for collection of the same will not be commensurate with the result likely to be achieved.

(e) to (g) As per the provisions of DPCO, 1987 and guidelines issued thereunder ,Small Scale Industrial Units are exempted from price control for Category II fomulations, subject to certain conditions.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजीनिवेश

3358. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश की दर अपेक्षाकृत थोड़ी रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सरकारी क्षेत्र के एककों में केन्द्रीय सरकार से पूंजी निवेश की दर बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) 1985-86 और 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के